औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में ऋण वसूली की तुलनात्मक स्थिति

890. श्री नागमणि:
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में ऋण वसूली की तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋणों की राशि में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिम राशि के प्रतिशत के रूप में अतिदेय निम्नलिखित हैं:

बड़े और मझौले उद्योग	15.76%
औद्योगिक सम्पदाओं सहित लघु उद्योग	24.46%
कृषि	24.95%

(ख) और (ग) ऋण के क्षेत्रीय अभियोजन संबंधी अंतरिम आंकड़ों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान कृषि कार्य के लिए बैंक ऋण की औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.7 प्रतिशत थी, जबकि उसी अवधि के दौरान उद्योग (लघु, मझौले और बड़े) के लिए वार्षिक वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि किसी क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की वृद्धि दर उस क्षेत्र विशेष के लिए उत्पादन के स्तर और साथ ही अतिरिक्त ऋण खपाने की इसकी क्षमता दोनों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकती है।

Report Regarding Disinvestment in CPSUs

891. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the Economic Times, Calcutta Edition, dated 25th June, 1996, regarding the alleged plan being prepered by the Finance Ministry about the disinvestment in blue chip CPSUs like SAIL, MTNL, Shipping Corporation of India etc.;

(b) if so, whether this report has any factual basis;

(c) whether it is in keeping with the principle of making such processes transparent by putting them before a disinvestment commission or making strong PSUs stronger to achieve the level of global majors; and

(d) if not, whether the report has been contradicted?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Government have approved the establishment of a Disinvestment Commission. Government will also keep in view transparency in future modes of disinvestment and strengthening the deserving PSUs.

Proposal for easier credit to Small Scale Sector

892. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide easier credit to small scale sector to help relieve production bottlenecks; and

(b) if so, the details of the proposal?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The reserve Bank of India (RBI) has reported that based on the recommendations of the Nayak Committee it has simplified the procedure for providing credit to small scale industrial (SSI) units. All commercial banks have been instructed by RBI to sanction working capital limits of less than Rs. one crore to SSI units on the basis of 20% of